खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई) : (क) से (छ) उपलब्ध सूचना के अनुसार जुलाई, 1991 से मार्च 1993 की अवधि में 2015 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किये गए थे। इन मामलों में अलग से किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती अत: इन्हें अस्वीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता। रोजगार पैदा करने, मूल्यवर्धन और निर्यात की संभावना को समझते हुए सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। कुछ खाद्य उद्योगों के लिए कच्चा माल देश में उपलब्ध है किंतु अच्छी श्रेणी के उत्पाद तैयार करने के लिये कुछ किस्मों का विकस करना भी आवश्यक है

Setting up of Small Agro based food processing Industries in Rural areas

1085. SHRI S.K.T. RAMACHANDRAN : Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that setting up of series of agro based food processing industries with available agricultural produce as raw materials can alone ease the stress of labour on farm lands and reduce the tendency of migration from rural to urban areas and improve the lots of the agriculturists and landless labourers in the rural areas; and

(b) if so, what steps are being taken by Government to set up such series of small agro based food processing industrial units in the rural areas suiting to the respective conditions of the local area concerned ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI) :

(a) and (b) Considering the potential for employment generation, value addition and export, Government have accorded high priority for development of agro food processing industries. While the Ministry of Food Processing Industries does not set up food processing industries directly in any State, it has formulated several developmental. Plan Schemes for the development of food processing industries, for implementation during the Eight Plan. Under these Schemes, financial assisstance is provided to State Government Organisations, Joint Sector Companies, Cooperatives Societies, Voluntry Agencies etc. for setting up/upgrading food processing industries. One of our Plan Schemes envisages setting up of food Processing Training Centres in rural areas, which will provide a 'Hands-on' experience in operating and managing a small unit.

मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संभावनाएं

1086. **श्री राधाकिशन मालवीय : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में फलों और सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है;

(ख) क्या सरकार ने इस राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के क्षेत्र में निवेश करने के संबंध में कोई आकलन किया है अथवा कराने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्योग के कौन-कौन से क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन दिए जाने का विचार है तथा यह प्रोत्साहन किस सीमा तक दिये जाने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। उदारीकरण के बाद अगस्त, 1991 से जनवरी, 1994 तक मध्य प्रदेश के मामले में 210 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किये गए हैं जिनमें करीब 18.68 करोड़ रु० का पूंजी-निवेश

और करीब 32,000 लोगों को रोजगार देना निहित है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के वास्ते आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें तैयार की हैं। इन स्कीमों के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने/उनका उन्नयन करने के लिए राज्य सरकार के सगठनों, संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों, सहकारी समितियों, स्वैच्छिक एजेंसियों आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस मंत्रालय की योजना स्कीमों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश स्थित फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की युनिटों को दी गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

फल और सब्जी संस्करण

	मध्य प्रदेश की दी गयी सहायता	45 लाख रु० की इक्विटी सहायता
1.	मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लि०, भोपाल (1990–91)	(बर्वई में फल और सब्जी प्रसंस्करण सयंत्र का सुदृढ़ करना)
2.	सतपुड़ा एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान (एस आई आर डी आई), भोपाल (1992–93)	2.585 लाख रु० की सहायता अनुदान (स्थान प्रयोगशाल के लिए)
3.	महिला चेतना मंच, भोपाल (1993–94)	5.90 लाख रु० का सहायता अनुदान (खुम्बी की खेती)
4.	मारफेड, भोपाल (1993–94)	72.00 लाख रु० का सहायता अनुदान (एन.सी.डी.सी. माध्यम से) (शीत–भंडारण की स्थापना के लिए)

फलों के उत्पादन में वृद्धि

1087 श्री राम जेठमलानी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन दशकों के दौरान देश में फलों के उत्पादन में 54.71 प्रतिशत तक वृद्धि हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 में फलों और सब्जियों का कितना-कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ग) देश में फलों और सब्जियों को कितनी मात्रा का उपभोग किये जाने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार ने फलों और सब्जियों की शेष मात्रा के प्रसस्करण हेतु उपयोग किए जाने हेतु देश में खाद्य प्रसस्करण उद्योग की क्षमता का आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त क्षमता कितनी है तथा क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा आवश्यक मात्रा के प्रसंस्करण किये जाने के बाद बची शेष मात्रा का उचित उपयोग करके उत्पादो को निरुत्साहित होने से बचाने के लिए उपाय कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण) उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) गत तीन दशकों में हुए फल और सब्जी के उत्पादन के कोई सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किंतु उपर्युक्त अवधि के दौरान उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि